आकाशवाणी
क्षेत्रीय समाचार
देहरादून (उत्तराखण्ड)
शनिवार 18.04.2026
समय 1305

मुख्य समाचार :–

- देहरादून में आढ़त बाजार–तहसील चौक सड़क चौड़ीकरण परियोजना में आई तेजी, 52 संपत्ति धारकों को 21 करोड़ रुपए का मुआवजा मिला।
- ऊधमसिंह नगर जिले के रुद्रपुर में हुई जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण की 22वीं बोर्ड बैठक में विकास से जुड़े विभिन्न प्रस्तावों पर चर्चा की गई।
- मसूरी में बढ़ती यातायात समस्या से निपटने के लिए नगर पालिका ने यातायात सुधार का प्रस्ताव रखा। शाम 5 बजे के बाद मॉल रोड पर वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी।
- पौड़ी गढ़वाल के सभी विकासखंडों में घर–घर जाकर गर्भवती महिलाओं की जांच करने के साथ ही संस्थागत प्रसव के लिए जागरूक किया जा रहा है।

आढ़त बाजार/परियोजना

राजधानी देहरादून में आढ़त बाजार–तहसील चौक सड़क चौड़ीकरण परियोजना के तहत तेजी से कार्य किया जा रहा है। मसूरी–देहरादून विकास प्राधिकरण के अनुसार परियोजना से प्रभावित 52 संपत्ति धारकों को अब तक लगभग 21 करोड़ रुपये का मुआवजा वितरित किया जा चुका है। मुआवजा मिलने के बाद इन संपत्ति धारकों ने अपनी संबंधित भूमि–संपत्तियों की रजिस्ट्री लोक निर्माण विभाग के नाम कर दी है। मसूरी–देहरादून विकास प्राधिकरण ने बताया कि शेष 34 संपत्ति धारकों के दस्तावेजों का परीक्षण पूरा कर लिया गया है और उनकी रजिस्ट्री की प्रक्रिया शीघ्र शुरू की जाएगी। कुल 410 प्रभावित संपत्तियों में से कई स्थानों पर स्वेच्छा से हटाने का कार्य भी शुरू हो गया है, जिससे निर्माण कार्य को गति मिली है। नए आढ़त बाजार में लगभग 95 प्रतिशत पार्किंग व्यवस्था तैयार हो चुकी है, जबकि अन्य विकास कार्य 80 प्रतिशत तक पूरा हो चुके हैं। शेष कार्यों को तेज गति से पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। प्राधिकरण के अनुसार पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाया जा रहा है, जिससे प्रभावितों का विश्वास मजबूत हुआ है। अधिकारियों ने कहा कि परियोजना का उद्देश्य केवल सड़क चौड़ीकरण नहीं, बल्कि शहर में यातायात दबाव को कम करते हुए एक सुव्यवस्थित और आधुनिक शहरी ढांचे का निर्माण करना है।

विकास प्राधिकरण बैठक

ऊधमसिंह नगर जिले के रुद्रपुर में जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण की 22वीं बोर्ड बैठक आयोजित की गई। कुमाऊं आयुक्त और प्राधिकरण के अध्यक्ष दीपक रावत की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में विकास से जुड़े विभिन्न प्रस्तावों पर चर्चा की गई। इस दौरान बागवाला में पीएम आवास योजना के तहत निर्माणाधीन एक हजार 872 फ्लैट को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए गए। प्राधिकरण के अध्यक्ष दीपक रावत ने बताया कि बैठक में जिले के ढांचागत विकास की कई योजनाओं के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।

जगणना प्र□क्षण

उत्तराखंड में जनगणना–2027 के तहत प्रशिक्षण और जन–जागरूकता गतिविधियों में तेजी लाते हुए राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में प्रगणकों और सुपरवाइजरों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में हरिद्वार जिले के झबरेड़ा, मंगलौर और बीएचईएल तथा पौड़ी गढ़वाल के बीरोंखाल और चैबट्टाखाल में प्रशिक्षण कार्यक्रमों और बैठकों का आयोजन किया गया। इन सभी गतिविधियों के माध्यम से जनगणना–2027 के सफल संचालन के लिए प्रशासनिक समन्वय, प्रशिक्षण की गुणवत्ता और जनभागीदारी को सुदृढ़ किया जा रहा है। वहीं, जनगणना कार्य को प्रभावी बनाने के लिए स्व–गणना के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से विभिन्न विभागों और संस्थानों के साथ संवाद भी स्थापित किया गया। राज्य सरकार ने नागरिकों से अपील की है कि वे स्व–गणना सुविधा का अधिक से अधिक उपयोग करें और इस राष्ट्रीय महत्त्व के कार्य में सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करें।

यातायात व्यवस्था

पहाड़ों की रानी मसूरी में बढ़ती यातायात समस्या से निपटने के लिए नगर पालिका ने सख्त कदम उठाए हैं। नगर पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी की अध्यक्षता में हुई बैठक में शहर के प्रमुख मार्गों को चरणबद्ध तरीके से वन–वे करने का प्रस्ताव रखा गया। सबसे बड़ा फैसला मॉल रोड को लेकर लिया गया है। अब शाम 5 बजे के बाद मॉल रोड पर सामान्य वाहनों की आवाजाही पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी और इसमें केवल आपातकालीन सेवाओं को छूट मिलेगी। जबकि स्थानीय निवासियों और जरूरतमंदों को शाम 6 बजे तक राहत दी जाएगी। साथ ही निवासियों के लिए विशेष पास की व्यवस्था भी की जाएगी।

संस्थागत प्रसव/जागरुकता

पौड़ी गढ़वाल में शत–प्रतिशत संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से सभी विकासखंडों में घर–घर जाकर गर्भवती महिलाओं की जांच करने के साथ ही संस्थागत प्रसव के लिए जागरूक किया जा रहा है। इसके तहत थलीसैण, पोखड़ा, एकेश्वर और खिरसू विकासखंडों के विभिन्न गांवों में स्वास्थ्य विभाग की टीमों द्वारा गृह भ्रमण के साथ ही आयुष्मान आरोग्य मंदिरों व उपकेंद्रों में कुल 56 गर्भवती महिलाओं की जांच की गई। इस दौरान गर्भवती महिलाओं के साथ ही उनके परिजनों को घर पर प्रसव के खतरों के बारे में जानकारी दी गई और संस्थागत प्रसव के लिए प्रेरित किया गया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. शिव मोहन शुक्ला ने बताया कि गृह भ्रमण के दौरान अभी तक 627 गर्भवती महिलाओं की निगरानी की जा चुकी है। इस दौरान गर्भवती महिलाओं को नियमित जांच के साथ ही समय पर अल्ट्रासाउंड कराए जाने आकस्मिक स्थिति में निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा का लाभ लेने, प्रसव के बाद जच्चा–बच्चा को घर तक छोड़ने के लिए सेवा और स्वास्थ्य परामर्श के लिए टोल फ्री सेवा आदि की जानकारी दी गई।

वनाग्नि

प्रदेश में गर्मी की शुरुआत होने के साथ ही जंगलों में आग की घटनाएं भी बढ़ने लगी हैं। मुख्य वन संरक्षक सुशांत कुमार पटनायक ने बताया कि 15 फरवरी से शुरू हुए फायर सीजन में अब तक राज्य के 100 से ज्यादा स्थानों पर जंगलों में आग लगने की घटनाएं सामने आ चुकी हैं और समय रहते अधिकांश आग पर काबू पा लिया गया। उन्होंने बताया कि अभी तक गढ़वाल मंडल से वनाग्नि के ज्यादातर मामले सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि विभागीय स्तर पर पहले से ही सभी टीमों को अलर्ट पर रखा गया है।

वनाग्नि/वाहन

उत्तरकाशी जिले में वनाग्नि की घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाने और वन्यजीवों की सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए जिला प्रशासन और वन विभाग ने एक बड़ी पहल की है। जिलाधिकारी प्रशांत आर्य ने जिला योजना वित्तीय वर्ष 2025–26 के अंतर्गत वन विभाग द्वारा खरीदे गए तीन अत्याधुनिक वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये विशेष वाहन 500 लीटर की टैंक क्षमता और उच्च दाब वाले पानी के पम्प से लैस हैं, जो दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में वनाग्नि पर त्वरित नियंत्रण पाने में सहायता करेंगे। इन वाहनों को उत्तरकाशी वन प्रभाग, अपर यमुना और टौंस वन प्रभाग पुरोला को सौंपे गए हैं। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने कहा कि ये वाहन वनाग्नि काल में आगजनी की घटनाओं को कम करने के साथ ही अन्य बहुउद्देशीय कार्यों में भी उपयोगी होंगे। वनाग्नि का सीजन समाप्त होने के बाद, इन वाहनों से पानी के पम्प हटाकर इनका उपयोग जंगलों में गश्त, राजकीय सामग्री के परिवहन और घायल

वन्यजीवों को रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थान तक पहुँचाने में किया जाएगा। उन्होंने कहा इस तकनीकी सुदृढ़ीकरण से जिले की अमूल्य वन संपदा का संरक्षण और बेहतर ढंग से हो सकेगा।